

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 526-तीन/14

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

१०.५.१५

यह निगरानी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

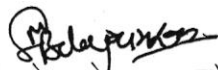
2/ आवेदक मुस० मित्ता बेवा जस्सू सेहर ग्राम सामरा तहसील पोहरी स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कुल कित्ता 08 कुल रकबा 7.84 हे० भूमि विक्रय करना चाहती है जो उसके द्वारा स्वयं व्यय पर खरीदी गयी है। आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के पश्चात उसके भूमिस्वामी स्वत्व में सर्वे कर 44.18 तथा 32 कुल रकबा 1.51 हे० भूमि शेष रहना दर्शाया है जो उसके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा क्रय कर उस पर नामान्तरण कराने के संबंध में किश्तबन्दी खतौनी बी-1 वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटो कापियाँ आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। आवेदक उक्त भूमि विक्रय कर अन्य शेष भूमि पर सिंचाई हेतु ट्यूब वेल लगाना चाहती है जिससे फसल का अच्छा लाभ मिल सके। विक्रय की जाने वाली असिंचित तथा


अनुपजाऊ होने से फसल का अच्छा लाभ नहीं होना दर्शाया गया है।

3/ प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की स्वयं खरीदी गयी भूमि है तथा भूमि विक्रय के बाद भी उसके भूमिस्वामी स्वत्व में 1.51 हे० भूमि शेष रहती है, इसलिये न्यायहित में प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है—

1. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हों।
2. आवेदक को विक्रय राशि का भुगतान रजिस्टार के समक्ष किया जावे।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति से भूमि का विक्रय अनुबंध किया गया है, उसी को भूमि का विक्रय किया जाय।

4/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त, ग्वालियर संभाग का अपील प्र०क० 06/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-01-14 तथा अपर कलेक्टर, शिवपुरी का आदेश दिनांक 05-09-13 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।


(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य
लोक अदालत


(एम०के०) सिंह
अध्यक्ष
लोक अदालत

